TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) A token provision of Rs. 5 lakhs has been made for the proposed Training Institute for Port Workers in the Seventh Plan.

(b) A blueprint of Training Insti-tuts is under preparation and site for locating Institute has been identified. However, it is too early to indicate the likely date by which the Institute is likely to start functioning because there are a number of formalities like clearance from the Department of Environment of Government of Maharashtra, Land Records Office etc., to be completed.

(c) Although the token provision made is not adequate, Bombay Port has been informed that the entire expenditure on account of this scheme can be accommodated within the overall Plan outlays.

Merger of SNIPES, NIS and SAI

912. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to merge the Society for National Institutes of Physical Education and Sports, National Institute of Sports/ Patiala and the Sports Authority of India into one body; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI-MATI MARGARET ALVA) fa) and (b) Tha Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala already functions under the Society for National Institutes of Physical Education and Sports (SNIPES). Although no decision has yet been taken on the merger of the SNIPEs and the Sports Authority of India (SAT) to bring them under one untied body stpes have been taken to bring them under a unified control to ensure coordination between their working.

मध्य प्रदेश में नये इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा वसूल किया जा रहा प्रति व्यक्ति शुल्क

913. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में हाल में दो नये इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये गये हैं जिनमें छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर नहीं किया जायेगा बल्कि प्रवेश उनको दिया जायेगा जो प्रवेश लेने के समय 10,000 रुपये का वार्षिक शुल्क दे सकें ;

(ख) क्या इन कालेजों की स्थापना "कैपिटेशन फ्री" पद्धति समाप्त करने की सरकार की नीति के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जहां तक केन्द्रीय सरकार को जानकारी है, मध्य प्रदेश में भिलाई में मात्र एक इंजीनियरी कालेज स्थापित किया गया है, जहां हर बच्चे से शिक्षा शुल्क के रूप में 10,000 रू० प्रतिवर्ष वसूल किए जाते हैं। राज्य सरकार के अनुसार, उपर्युक्त उल्लिखित शुल्क के भुगतान के साथ दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर दाखिल किया जाता है।

(ख) और (ग) इस कालेज की स्थापना केन्द्रीय सरकार की उस नीति के अनुरूप नहीं है जो प्रतिव्यक्ति और/अथवा अधिक शुल्क वसूल करने के विरुद्ध है। तथापि, राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सलाह का